International Journal of Education and Science Research
Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-7, Issue-4 August- 2020, P-ISSN 2348-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

मध्य प्रदेश के सागर जिले में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों का संक्षिप्त अध्ययन

[1]Jyoti Bairagi, [2]Dr.Gulab Singh Parmar
[1]Research Scholar, [2]Supervisor
Career Point University
Kota, Rajasthan

सार–

औद्योगिक दृष्टि से सागर जिला प्रदेश के पिछड़े जिले की ''स'' श्रेणी में आता है। यहां औद्योगिक विकास की दर में पर्याप्त दर में नहीं हो पाया है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस कारण यहाँ पर वृहद् उद्योगों की तुलना में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है, पर वह गिने चुनें हैं। जिले में वर्तमान में 5 लाख रूपये से अधिक स्थाई पूंजी विनियोजन करने वाली पंजीकृत लघु इकाईयां 218 हैं। सागर जिला वर्तमान में बुन्देलखण्ड के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केन्द्रों के रूप में माना जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व सागर विश्वविद्यालय होने के अतिरिक्त और नहीं था, लेकिन आज सागर समूचे बुन्देलखण्ड क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्य और औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है। सागर को इस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय यहां के उद्यमियों को है जिन्होंने अपनी मेहनत, उद्यामिता, एवं लगनशीलता से विकास का पथ प्रशस्त किया है। सागर में स्ट्राबोर्ड, बेजीटेबिल आयल, रिफाइंड आयल, सिंगल सुपर फॉस्फेट की एक–एक मध्यम इकाईयों के अतिरिक्त भारत ओमान रिफायनरी आयल नामक बृहत् उद्योग के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण लघु इकाईयां है। जिनसे मिलकर यहाँ का औद्योगिक परिदृश्य निर्मित होता है। स्थानीय लोगों के पास पूंजी है परन्तु उद्योगों में लगाने में संकुचाते हैं। जिले में उद्यामिता की कमी नहीं है। इसलिए जिले में विभिन्न सुवधायें उपलब्ध कराके औद्योगिक वातावरण बनाया जा रहा है। नई आर्थिक नीति के लागू होने से जिले का औद्योगिक विकास असंतुलित रहा है। इस असंतुलित विकास की दर को संतुलित करने में वृहत् और मध्यम उद्योग सक्षम हो रहे हैं। जिले में एक मात्र वृहद् उद्योग एवं मध्यम उद्योग इस भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं, भले ही उन्हें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिली है।

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश भारत के बीचों–बीच हृदय स्थल के सामन फैला है। यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। एक नवम्बर सन् 2000 को मध्यप्रदेश राज्य का का विभाजन करके नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया। वर्ष 2011(प्रा.) की जनगणना के 72597565 अनुसार है। मध्यप्रदेश राज्य पांच प्रमुख राज्यों तथा उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। वर्तमान में राज्य में 50 जिले, 342 तहसील, 313 विकासखण्ड तथा, 459 जनपद पंचायते तथा 50 जिला पंचायते कार्यरत है। सन् 2011 में (प्रा.) जनगणना अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 72597565 है जिसमें से 37612920 पुरूष एवं 34984645 महिलाएं हैं। पिछले एक दशक 2010–11 में राज्य की जनसंख्या 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य में पुरूष–स्त्री अनुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाएं) राज्य में जनसंख्या का घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। राज्य में जनगणना 2011 (प्रा.) के अनुसार साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत् है। इस अवधि में पुरूष एवं महिला साक्षरता दर क्रमशः 80.5 प्रतिशत् एवं 60.1 प्रतिशत है। इस प्रकार पिछले दशक में राज्य की साक्षरता दर में उल्लेखित प्रगति हुई है। कुदरत ने मध्यप्रदेश को अपनी सौगात से मालामाल किया है। पर्वतों, नदियों में एक अनूठा लुभावनापन है। यही कारण है कि यह प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा से घनी है। प्राकृतिक साधनों की इतनी विपुलता पर भी यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में दूसरे स्थान पर आता है।

मध्यप्रदेश से परम्परागत उद्योग एवं हेण्डीक्राफ्ट उद्योगों के लिए विशेष उपलब्धि हासिल की है। यहाँ के बने हेण्डीक्राफ्ट के समान विश्वविख्यात हैं। प्रदेश का प्रत्येक शहर व गांव इस क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेषता रखता है। राज्य के कुछ प्रमुख हेण्डीक्राफ्ट उद्योग केन्द्रों की श्रृंखला में–बाघ, बालाघाट, भोपाल, चंदेरी, ग्वालियर, विदिशा, सरगुजा, महेश्वर, मन्दसौर, मरैया आदि प्रमुख हैं। यहां कपड़े पर छपाई, रेशम साड़ी पर छपाई, मूर्तियाँ, गलीचे, जरी, बटुआ, पीतल की टेबलें, महेश्वरी साड़ी एवं लकडी के सजावटी समान आदि बनाये जाते हैं।

उपरोक्त उद्योगों के प्रदेश में कार्यरत होने पर भी प्रदेश में औद्योगीकरण का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इस कारण प्रदेश का औद्योगिक विकास असंतुलित है। राज्य में औद्योगिक के प्रयास किये जा रहे है। फलस्वरूप अधिक पूंजी निवेश को आर्कषित करने, क्षेत्रीय विकास में संतुलिन तथा आम जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने तथा राज्य को औद्योगिक रूप से अग्रणी प्रदेश के समकक्ष लाने का लक्ष्य रखा गया है। इन दायित्वों की पूर्ति हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक सहायता केन्द्रों तथा लघु उद्योगों के लिए जिला स्तर पर सभी सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए एकल एजेन्सी प्रणाली व एस्कार्ट सर्विस लागू की है।

जिले में मध्यम और वृहद उद्योगों का महत्व

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वहां विद्यमान उद्योगों का काफी महत्व होता है। क्योंकि विकास की ऊँची दर को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कारक औद्योगीकरण ही है और औद्योगीकरण में लघु एवं कुटीर, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

वृहद् उद्योगों की महत्वता को डॉ.ए.एन. अग्रवाल ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा कि–''देश के विकास में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिति अत्याधिक महत्वपूर्ण होती। उनकी प्रांसगिकता इतनी अधिक है कि क्षेत्रों में तो इन्हें अपरिहार्य माना जाता है।''

पूर्व में ही कहा गया है कि सागर जिला पिछड़े जिलों की श्रेणी ''स'' में आता है तथा यहां उद्योग का अपेक्षानुकूल विकास पर्याप्त नहीं हो पाया है। सागर जिला एक कृषि प्रधान जिला है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। यहाँ पर वन सपंदा व पशु–धन संपदा पर्याप्त है, परन्तु यहाँ पर खनिज संपदा का अभाव है। उपरोक्त स्थितियों के कारण यहां पर वृहद् उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। वर्तमान में बीना तहसील के आगासौद ग्राम में एकमात्र बृहत् उद्योग ऑयल रिफायनरी नाम से स्थापित है। इसके अलावा जिले में मध्यम उद्योगों का विस्तार भी हुआ है। चूंकि इनकी संख्या बहुत ही कम हैं। फिर भी औद्योंगिक विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिले में सन् 2019 तक केवल चार उद्योग इकाईयां मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। बाद में दो उद्योगों का उत्पादन क्षमता व रोजागर स्तर को देखकर शासन ने उन्हें भी मध्यम उद्योग में बदल दिया। इस प्रकार जिले में वर्तमान में छः उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

सागर जिले में स्थापित मध्यम उद्योगों की श्रृंखला में सर्वप्रथम जनवरी सन् 1981 में उत्पादन कार्य शुरू करने वाले उद्योग इकाई ग्राम किशनपुरा में मेसर्स पेपर बोर्ड मिल के नाम से 96.80 लाख रूपये पूंजी विनियोजित कर स्थापित की गयी। यह उद्योग इकाई स्ट्राबोर्ड का उत्पादन करती है। जिले में दूसरी मध्यम उद्योग इकाई 09/04/1984 को 134.08 लाख रूपयें विनियोजित करके ग्राम भैंसा में मेसर्स सागर सोया प्रोडक्टस के नाम से स्थापित हुई। इस उद्योग इकाई में वेजिटेबिल ऑयल का निर्माण किया जाता है। जिले में अगली मध्यम इकाई 19/11/1992 को 92.94 लाख रूपये विनियोजित करके मेसर्स अरविंद फुड प्रोडक्टस लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई। इस उद्योग इकाई में रीफाईन्ड ऑयल का उत्पादन होता है। जिले में चौथी मध्यम उद्योग इकाई दिनांक 28/06/1999 को ग्राम रजौआ में 346.0 लाख रूपये की पूंजी निवेश से मेसर्स मध्य भारत एग्रों प्रोडक्टस लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई। यह उद्योग इकाई सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन करती है। जिले में सन् 2001–02 को दो लघु उद्योगों इकाईयों को मध्यम उद्योग इकाईयों में परिवर्तित किया गया। इन उद्योगों में प्रथम सनमति फारेस्ट इंडस्ट्रीज ग्राम सनोधा में कत्था उत्पादन करने वाली तथा द्वितीय रेवती मिनरल केमीकल्स ग्राम हीरापुर में सिंगल फास्फेट का उत्पादन करती है।

उपरोक्त उद्योग इकाईयाँ जिले के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होने का प्रयास कर रही हैं। इनकी महत्वता को हम निम्न बिन्दुओं में प्रकट कर सकतें हैं :–

1. जिले की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव–जिले में मध्यम उद्योग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। ये उद्योग जिले में प्राप्त

कच्चे माल तथा दूसरे जिलों से कच्चेमाल का आयात करके उत्पादन कार्य करते हैं। इनके उत्पादन का स्तर लघु एवं कुटीर उद्योगों की तुलना में अच्छा होता है। यही कारण है कि इनके द्वारा बनाये गये माल का विक्रय आसानी से हो जाता है। इससे औद्योगिक विकास में वृद्धि हो रही है और जिले की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

2. दूसरे जिले की मुद्रा अर्जित करने में सहायक–जिले में जो मध्यम आकार के उद्योग उत्पादन कार्य कर रहे हैं। वे अपने द्वारा बनाये गये माल को दूसरे जिलों में निर्यात करते हैं जिससे दूसरे जिलो की मुद्रा जिले को प्राप्त होती है। हालाकि इसका प्रतिशत् कम होता है फिर भी कहावत ठीक है कि बूंद–बूंद से घड़ा भरता है। इस प्रकार जिले में मध्यम उद्योग मुद्रा अर्जित के साधन भी हैं।

3. जिले की आय बढ़ाने में सहायक–जिले में जो मध्यम उत्पादन कार्य में संलग्न हैं वह जिलें की आय बढ़ाने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं क्योंकि इन उद्योगों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन कर उसका विक्रय होता है तो उद्योगों को आय प्राप्त होती है जो कि जिले की आय बढ़ाने में सहायक होती है।

4. जिले व अन्तर्जिले में उत्पादित माल की पूर्ति करना–जिलें व अन्य जिलों के मध्यम उद्योग जिले व अन्य जिलों में उत्पादित माल की पूर्ति करते हैं, जिससे उनके द्वारा उत्पादित किए गए माल की मांग बनी रहती है। इस मांग की मात्रा भले ही कम हो परन्तु जिले के लिए सराहनीय बात है।

5. औद्योगिक विकास बढ़ाने में सहायक–जिले में व्याप्त मध्यम उद्योग औद्योगीकरण में सहायक है। इससे संबंधित नए उद्योग की स्थापना होने लगी है। यह कदम औद्योगिक विकास के लिए सहायक है।

6. जिले में प्राप्त कच्चे माल की खपत–सागर जिला एक कृषि प्रधान जिला होने से यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए यहाँ पर तिलहन फसलों (सोयाबीन) व खाद्य फसलों की पैदावार अधिक होती है। इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में ग्राम भैंसा में स्थापित मेसर्स सागर सोया प्रोडक्ट एवं अरविंद फुड प्रोडक्टस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जिले के लगभग 70 प्रतिशत् कच्चे माल की खपत इन्हीं उद्योगों द्वारा की जाती है।

7. जिले की वन सपंदा से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग–सागर जिला वन सपंदा में एक धनी जिला है। यहाँ के वनों से तेन्दू के वृक्ष, सागौन, साज, खैर, महुआ, धवा, बेल, बबूल, जामुन साज, महुआ आदि के वृक्ष हैं। जिले के लगभग 347277 हेक्टेयर में वन हैं। इन वनों से प्राप्त कच्चा माल खैर, बांस व अन्य लकड़ियॉ का उपयोग सनमति फारेस्ट इंटरस्ट्रीज सानौधा जो कि कत्था का निर्माण करती है एवं सेन्ट्रल पेपर बोर्ड मिल किशनपुरा जो कि स्ट्राबोर्ड का निर्माण करती है के द्वारा हो जाती है। अन्य मध्यम वन संपदा से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं परन्तु उनका प्रतिशत् कम हैं।

8. उपभोक्ताओं का उद्योग द्वारा निर्मित माल की पूर्ति–उपभोक्ता वर्ग को मध्यम वर्ग के उद्योगों द्वारा माल की पूर्ति की जाती है। सेन्ट्रल पेपर बोर्ड मिल (किशनपुरा) द्वारा सम्पूर्ण जिले में स्ट्राबोर्ड की पूर्ति, सागर सोया प्रोडक्टस (भैंसा) द्वारा रिफाईन्ड ऑयल की पूर्ति,मध्यम एग्रों प्रोडक्टस लिमिटेड (रजौआ) द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट की पूर्ति,सनमति फारेस्ट इंडस्ट्रीज (सानौधा) द्वारा कत्था एवं रेवती मिरनल्स केमीकल्स (हीरापुर) द्वारा जिले के उपभोक्ताओं को सिंगल फास्फेट की पूर्ति होती है। इस कारण आवश्यक उपभाक्ता वर्ग को उत्पाद आसानी से प्राप्त हो जाता है।

9. औद्योगीकरण में सहायक–मध्यम उद्योग औद्योगीकरण में सहायक हैं। इन उद्योगों की जहाँ–जहाँ पर स्थापना हुई है, वहां पर औद्योगिक वातावरण निर्मित होने लगा है। इस तथ्य के लिए यही काफी है कि ग्राम भैंसा में पहले सागर सोया प्रोडक्टस नाम से वेजीटेबल ऑयल की मध्यम उद्योग इकाई स्थापित की गई थी। बाद में औद्योगिक वातावरण बनने के कारण यहीं पर दूसरा मध्यम उद्योग अरविंद फुड प्रोडक्टस लिमिटेड के नाम से रीफाईन्ड

ऑयल की उद्योग इकाई की स्थापना की गई।

10. श्रमिकों का जीवन स्तर उच्च होता है–जिले में स्थापित मध्यम उद्योगों में संलग्न श्रमिकों का जीवन स्तर अन्य श्रमिकों की तुलना में उच्च होता है क्योंकि ये उद्योग इकाईयां लगभग वर्षभर उत्पादन कार्य करती हैं, जिससे इसमें जो संलग्न (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) श्रमिकों को वर्ष पर रोजगार मिलता है। नियमित रोजगार मिलने से उनकी आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होने से उनका जीवन स्तर ऊँचा रहता है।

11. अप्रत्यक्ष रूप से यातायात व संचार के साधनों का विकास होता है, क्योंकि जब इन उद्योगों के लिए कच्चा माल उद्योगों तक, उत्पादित माल विभिन्न स्थानों पर जाता है तथा इनके द्व ारा उत्पादित माल की जानकारी मूल्य आदि के लिए फोन का उपयोग होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से यातायात व संचार के साधनों का उपयोग होता है जिससे सरकार एवं साधन पतियों को आय प्राप्त होती है।

12. मध्यम उद्योगों द्वारा मांग से अधिक निर्मित माल जब विभिन्न जिलों में जाता है तो जिले की एक विशिष्ट पहचान बनती है।

13. जिले में औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए–जिले में औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए मध्यम व वृहद् उद्योगों की स्थापना होना जरूरी है ताकि जिले में औद्योगिक विकास हो सके।

14. सागर जिले को विकसित जिलों की श्रेणी में लाने के लिए–सागर जिले को विकसित श्रेणी में लाने के लिए यहां पर वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना होना जरूरी है। चूंकि सागर जिला पिछड़े जिले की श्रेणी (स) में आता है। इसे विकसित जिलों की श्रेणी में लाने के लिए जिले में व्याप्त संसाधनों के आधार पर मध्यम उद्योग स्थापित करने होंगे, जिससे जिले में औद्योगिक विकास के आसार नजर आने लगें।

निष्कर्ष–

उद्योग की स्थापना यदि जिले में हो जाती है तो जिले में वास्तव में औद्योगिक क्रांति के आसार नजर आने लगेंगे और सागर जिला विकसित जिलों की सूची में शामिल होने वाले जिलों में स्थान बनाने वाला प्रबल दारवरेदार कहलाने के काबिल हो जायेगा। पर यह सभी संभव है जब सागर जिले के उद्यमी व साहसी नये–नये उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी लगाने को तैयार हो सरकार का योगदान, वित्तीय संस्थाओं की प्रबल भूमिका, अनुकूल औद्योगिक वातावरण उत्पादित माल की खपत के लिए बाजार कुशल प्रबंधन व श्रम शक्ति के अलावा प्राकृतिक सहयोग जैसी अनुकूल परिस्थितियां एक साथ उपलब्ध हो।

सन्दर्भ सूची

होस्मर, एल0 एस0 – दि इन्टरप्रिन्योरियल फंक्शन प्रेन्टिस हॉल न्यू जर्सी, 1977
लघु उद्योग विकास विभाग भारत सरकार – ए हैण्डबुक ऑफ सरल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट, 1988
लघु उद्योग विकास विभाग भारत सरकार – ए हैण्डबुक फॉर एक्सटेन्सिव सर्विसेज
हसबैण्ड एण्ड डाकरे – इन्ट्रोडक्शन टु बिजनेस फाइनेन्स, 1987
हाबार्ड एण्ड उपटोन – मॉर्डन कॉरपोरेशन फाइनेन्स, 1987
डेनिस, राबर्टसन – कन्ट्रोल ऑन इण्डस्ट्री
मरे डी॰, ब्राइस – इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट
फ्लोटेन्स, पी0 एम0 – इकोनोमिक्स एण्ड सोशियोलॉजी ऑफ इण्डस्ट्री
मिल्टन, फ्रेण्डमैन – कैपिटेलिज्म एण्ड फ्रीडम
कनका, एस0एस0 – इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट इन कुमायूं, 1988